

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
उत्तरकाशी।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 6-11-2008

विषय:-स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट  
नैताला उत्तरकाशी को पट्टे पर भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5008/21-7(2007-08) दिनांक 29.5.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट नैताला उत्तरकाशी को गरीब, अनाथ बच्चों, वृद्धों आदि की निशुल्क शिक्षा दीक्षा, चिकित्सा सहायता आदि जनहित के कार्यों हेतु ग्राम नैताला उत्तरकाशी में स्थित उत्तराखण्ड सरकार के नाम नॉन जेड0ए0 खतोनी खाता संख्या-45 में दर्ज खसरा नम्बर 4129 रकबा 0.043 हेक्टेयर भूमि शासनादेश संख्या-258/16 (1)/73-रा-1 दिनांक 09 मई, 1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1 -1(60)/93-रा-1 दिनांक 12 सितम्बर, 97 में निहित प्राविधानों एवं वर्तमान बाजार दर के दो गुने के बराबर एकमुश्त नजराना (PREMIUM) जमा करने तथा नई दरों पर निकाली गयी मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया नियत करके निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
- 2- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा।
- 3- नजराने की धनराशि इस शासनादेश के निर्गत होने के उपरान्त तत्काल अथवा अधिकतम 03 (तीन) माह के भीतर जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
- 4- भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- 5- प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा0-6 दिनांक 09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्राण्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए ही होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा, तथा सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।

- 6- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को न रह जायेगी तो भूमि निर्माण (Structure) सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय न होगा।
- 7- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो, तो भूमि/भवन सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
- 8- आवंटित भूमि की लीज डीड कराने से पूर्व वन विभाग के सक्षम अधिकारी की भूमि अनापत्ति प्राप्त की जायेगी, एवं उसी खसरा नम्बर की भूमि आवंटित की जायेगी जो जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित की गई है।
- 9- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त विन्दु सं० 01 से 08 तक की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर आदि देय नहीं होगा।
- 10- उक्त आवंटन किसी नीति के अधीन नहीं किया जा रहा है। अतः ऐसे अन्य प्रस्तावों पर इसे उदाहरण स्वरूप नहीं लिया जा सकता है।
- 2- उक्त आदेशों का तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)  
अपर. सचिव।

संख्या 1235/18(1)/08-2(8)/2008 एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
- 3- स्वामिनी प्रमानंद सरस्वती अध्यक्षा तपस्यालयम आश्रम मैनेजिंग ट्रस्टी गंगा कुटीरम ट्रस्ट नैताल उत्तरकाशी।
- 4- ✓ निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(सन्तोष वैडोनी)  
अनुसचिव।